



BACKGROUNDERS

Press Information Bureau
Government of India

वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में भारत की बढ़ती भूमिका

28 जनवरी, 2026

मुख्य बिंदु

- प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों 25,400 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं, जिससे देशभर में लगभग 100% सीजीडी भौगोलिक कवरेज संभव हो पाता है।
- इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 में इथेनॉल का मिश्रण 19.05% तक पहुंच गया, जो 20% के राष्ट्रीय लक्ष्य के करीब है।
- पीएमयूवाई का दायरा बढ़कर 10.41 करोड़ परिवारों तक पहुंच गया है, और एलपीजी रिफिल दरों में वृद्धि निरंतर उपयोग का संकेत दे रही है।
- भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 वैश्विक हितधारकों को ऊर्जा सुरक्षा और संक्रमण संबंधी मुद्दों की जांच करने के लिए एक मंच पर लाया

बदलते विश्व में भारत की ऊर्जा अनिवार्यता

ऊर्जा आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक विकास और मानव कल्याण के लिए मूलभूत आवश्यकता है। यह औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएँ, डिजिटल कनेक्टिविटी और दैनिक घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करती है। भारत, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यह गतिशीलता, रसद और औद्योगिक गतिविधियों में पेट्रोलियम के निरंतर महत्व को दर्शाता है। इसके साथ ही, 2035 तक भारत की ऊर्जा मांग लगभग किसी भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ने का अनुमान है। यह भी अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में वृद्धि का 23 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भारत का होगा, जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक होगा।

इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, भारत ने नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढंगे के विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा के रास्तों के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। जून

2025 में, भारत ने पेरिस समझौते के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (एनडीसी) के तहत अपने 2030 के लक्ष्य से पांच वर्ष पहले ही, अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाशम ईंधन स्रोतों से हासिल कर लिया। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सुधार, ऊर्जा बुनियादी ढांचे का विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा की तीव्र वृद्धि सामूहिक रूप से आर्थिक विकास, रोजगार सर्जन और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भारत की उभरती भूमिका को बढ़ावा दे रहे हैं।

हाइड्रोकार्बन ऊर्जा शासन और क्षेत्रीय सुधार

भारत की ऊर्जा मांग में लगातार वृद्धि के साथ, ऊर्जा परिवर्तन की प्रभावशीलता न केवल बुनियादी ढांचे के विस्तार और स्वच्छ ईंधन पर निर्भर करती है, बल्कि ऊर्जा मूल्य शृंखला में इसके शासन और नियामक ढांचे की मजबूती पर भी निर्भर करती है। निवेश आकर्षित करने, परियोजनाओं की समयसीमा कम करने और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नीतियां, पूर्वानुमानित नियम और सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। इसी पृष्ठभूमि में, भारत ने ऊर्जा शासन को आधुनिक बनाने और इसे बदलते बाजार की स्थितियों और परिवर्तन की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए कई सुधार किए हैं।

भारत का हाइड्रोकार्बन क्षेत्र अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम खंडों में फैला हुआ है। अपस्ट्रीम खंड में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन शामिल है। मिडस्ट्रीम खंड में ईंधन का परिवहन और भंडारण शामिल है, जबकि डाउनस्ट्रीम खंड में शोधन और वितरण शामिल हैं। इन सभी खंडों में सुधारों का उद्देश्य दक्षता में सुधार, आपूर्ति सुरक्षा को बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की ओर क्रमिक परिवर्तन को समर्थन देना है।

हाइड्रोकार्बन ऐसे रासायनिक यौगिक हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं। ये कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, एलपीजी और सीएनजी जैसे प्रमुख ऊर्जा स्रोतों के मुख्य घटक हैं और रोजमरा की जिंदगी में बिजली, परिवहन और उद्योग में उपयोग होने वाले कई ईंधनों का आधार बनते हैं।

अपस्ट्रीम क्षेत्र में सुधार:

- तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) संशोधन अधिनियम, 2025: ओआरडीए (संशोधन) अधिनियम, 2025 प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, एकीकृत ऊर्जा विकास को सक्षम बनाकर और निवेशकों का विश्वास मजबूत करके भारत के अपस्ट्रीम नियामक ढांचे का आधुनिकीकरण करता है। इस सुधार का उद्देश्य घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करना और स्थिर, पारदर्शी नीतिगत वातावरण को बढ़ावा देना है।

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली, 2025: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली, 2025 तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए आधुनिक और पारदर्शी नियामक ढांचा प्रदान करती है। ये नियम व्यापार करने में सुगमता को सुदृढ़ करते हैं, नियामकीय निश्चितता में सुधार करते हैं और भारत के ऊर्जा सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करते हैं।

ओआरडीए (संशोधन) अधिनियम, 2025 के लागू होने और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली, 2025 की अधिसूचना के साथ इस क्षेत्र में सुधार हुआ। हाइड्रोकार्बन खोज लाइसेंसिंग नीति के तहत, 3.78 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 172 ब्लॉक आवंटित किए गए, जिससे लगभग 4.36 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश हुआ। भूकंपीय सर्वेक्षण, ड्रिलिंग कार्यक्रम और सरकार द्वारा वित्त पोषित पहलों के माध्यम से अन्वेषण गतिविधियों में तेजी आई।

मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सुधार:

मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में सुधारों का ध्यान ईंधन परिवहन में सुधार, मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित रहा है।

- एकीकृत पाइपलाइन टैरिफ (यूपीटी): "एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक शुल्क" नीति के तहत 2023 में शुरू किया गया यूपीटी, गैस परिवहन लागत में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया था। यूपीटी प्रणाली राष्ट्रीय गैस ग्रिड में परिवहन शुल्क को मानकीकृत करती है, और पहले की दूरी-आधारित टैरिफ संरचना को प्रतिस्थापित करती है। दिसंबर 2025 तक, लगभग 90 प्रतिशत परिचालन पाइपलाइनों यूपीटी के अंतर्गत आती हैं, जिससे प्राकृतिक गैस की सामर्थ्य और प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार होता है।

Powering a Nation: India's 2025 Energy Milestones



Enhancing Energy Access & Safety for Citizens

10.35 Crore Families



Benefit from Clean Cooking Fuel.

Under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana program as of Dec 2025.

12.12 Crore



Free LPG Safety Checks Conducted.

A nationwide campaign significantly enhanced consumer safety and awareness.

90,000+



Fuel Retail Outlets Modernized.

Enabled with digital payments and equipped with public toilet facilities.

Building a Sustainable Energy Future

25,429 km



Gas Pipeline Network Now Operational.

A major step towards the "One Nation, One Grid, One Tariff" vision.



India's First ISCC CORSIA Certification for SAF Production Achieved.

Indian Oil Corporation certified at Panipat Refinery



Major Upstream Reforms Enacted.

Through the new Oilfields Amendment Act and Petroleum & Natural Gas Rules.

Source: Ministry of Petroleum & Natural Gas

Data as of 26 December 2025

अवसंरचना विस्तार के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना

शासन सुधारों के साथ-साथ, ईंधन आपूर्ति शृंखलाओं, गैस कनेक्टिविटी और गतिशीलता प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए देश भर में ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे ऊर्जा तक पहुंच में वृद्धि, प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में योगदान मिला है।

ईंधन और गैस अवसंरचना:

- देशव्यापी ईंधन खुदरा नेटवर्क का विस्तार 2014 में लगभग 52,000 आउटलेट्स से बढ़कर 2025 तक एक लाख से अधिक हो जाएगा, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक ईंधन की उपलब्धता में सुधार होगा।
- स्वच्छ ईंधन अवसंरचना में तीव्र वृद्धि देखी गई, जिसमें सीएनजी स्टेशनों की संख्या लगभग 968 से बढ़कर 8,477 से अधिक हो गई और पीएनजी घरेलू कनेक्शनों की संख्या 25 लाख से बढ़कर 1.59 करोड़ से अधिक हो गई, जिससे स्वच्छ गतिशीलता और घरेलू ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा मिला।
- एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड की परिकल्पना के तहत, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार 25,400 किलोमीटर से अधिक तक हो गया है, और अतिरिक्त 10,459 किलोमीटर पाइपलाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे पूरे भारत में गैस का परिवहन संभव हो सकेगा।
- एकीकृत गैस ग्रिड ने 100 प्रतिशत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) भौगोलिक क्वरेज का समर्थन किया है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को मजबूती मिली है।

पेट्रोलियम विपणन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अवसंरचना:

- 90,000 से अधिक खुदरा दुकानों में डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराकर पेट्रोलियम विपणन अवसंरचना को मजबूत किया गया, जिसे 2.71 लाख से अधिक पीओएस टर्मिनलों का समर्थन प्राप्त है।
- घर-घर ईंधन वितरण को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में, 3,200 से अधिक ईंधन टैंकरों को चालू किया गया।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएएमई) फेज-II के तहत रिटेल आउटलेट्स पर 8,932 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के साथ हुआ है, साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा 18,500 से अधिक अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

लॉजिस्टिक्स और मार्ग संबंधी सुविधाएं:

- सड़क सुरक्षा, विश्राम सुविधाओं और लॉजिस्टिक्स कर्मचारियों के कल्याण में सुधार के लिए 500 से अधिक अपना घर ट्रक चालकों के लिए रास्ते में मिलने वाली सुविधाओं की स्थापना की गई।
- 1 नवंबर 2025 तक 1,064 एकीकृत ऊर्जा स्टेशन चालू किए गए, जो प्रमुख परिवहन गलियारों के साथ पारंपरिक ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा विकल्प भी प्रदान करते हैं।

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और कम कार्बन वाले मार्ग

ऊर्जा तक पहुंच और बुनियादी ढांचे के विस्तार ने भारत की ऊर्जा प्रणाली की भौतिक नींव रखी है। इसके साथ बढ़ती मांग को पूरा करते हुए ऊर्जा उपयोग की कार्बन तीव्रता को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और कम कार्बन उत्सर्जन वाले मार्ग ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

भारत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के साथ-साथ वैकल्पिक और कम कार्बन वाले ईंधनों को मिलाकर विविध दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 2014 से अब तक लगभग 1.59 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, 813 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है और 270 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ है। यह आयात पर निर्भरता और उत्सर्जन को कम करने में जैव ईंधनों की भूमिका को दर्शाता है।

जैव ईंधन पारंपरिक ईंधनों और स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं, जिससे मौजूदा वाहन और ईंधन अवसंरचना में बड़े बदलाव किए बिना उत्सर्जन में कमी लाना संभव हो जाता है। जैव ईंधनों के साथ-साथ, भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तीव्र वृद्धि और ग्रिड आधुनिकीकरण के समर्थन से हरित हाइड्रोजन, टिकाऊ ईंधन और कम कार्बन वाली अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में भी पहल को बढ़ावा दे रहा है। ये प्रयास भारत के 2070 के नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप हैं, साथ ही ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करते हैं।

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 को 2022 में संशोधित किया गया था, इसने पेट्रोल में 20 प्रतिशत ऐथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 2030 से बढ़ाकर ऐथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2025-26 कर दिया। ऐथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत, 31 जुलाई 2025 तक औसत ऐथेनॉल मिश्रण 19.05 प्रतिशत तक पहुंच

गया, जबकि जुलाई 2025 में यह 19.93 प्रतिशत हासिल किया गया, जो लक्ष्य की ओर स्थिर प्रगति को दर्शाता है।

ऊर्जा परिवर्तन के परिणाम घरेलू स्तर पर स्वच्छ ईंधनों को अपनाने पर भी निर्भर करते हैं, विशेष रूप से खाना पकाने में, जहां पारंपरिक ईंधन के उपयोग से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तदनुसार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा तक पहुंच का काफी विस्तार किया गया है, जिसके लाभार्थियों की संख्या जनवरी 2026 तक लगभग 10.41 करोड़ तक पहुंच गई है। एलपीजी कवरेज की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दी है, साथ ही एक ही वंचितता घोषणा के माध्यम से पात्रता प्रक्रिया को सरल बनाकर पहुंच को तेज और अधिक समावेशी बनाया है।

प्रारंभिक उपलब्धता के बाद खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन को निरंतर अपनाने के लिए इसकी सामर्थ्य सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर ₹300 की लक्षित सब्सिडी के माध्यम से प्रति वर्ष नौ बार तक ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करके सामर्थ्य सुनिश्चित की जा रही है। परिणामस्वरूप, एलपीजी के उपयोग में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जिसमें प्रति व्यक्ति औसत खपत 2019-20 में लगभग तीन बार ईंधन भरने से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रति वर्ष 4.85 बार ईंधन भरने तक पहुंच गई है, जो खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन को अधिक व्यापक रूप से अपनाने का संकेत देती है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी में एसएएफ उत्पादन के लिए इंटरनेशनल स्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन (आईएससीसी) कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (सीओआरएसआईए) प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई, जिसके बाद एसएएफ आपूर्ति के लिए एयर इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

सतत विमानन ईंधन (एसएएफ): सांकेतिक मिश्रण लक्ष्य: केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन ट्रबाइन ईंधन में एसएएफ के लिए सांकेतिक मिश्रण लक्ष्य 2027 से 1 प्रतिशत, 2028 से 2 प्रतिशत और 2030 से 5 प्रतिशत निर्धारित किए हैं।

भारत का वैशिक ऊर्जा नेतृत्व और भविष्य के लिए प्रतिबद्धता

भारत के ऊर्जा परिवर्तन की प्रगति के साथ, वैशिक बाजार के घटनाक्रमों को समझने, कार्यान्वयन के अनुभवों को साझा करने और ऊर्जा सुरक्षा एवं स्थिरता पर सामूहिक प्रतिक्रियाओं में योगदान देने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंचों के साथ जुड़ाव महत्वपूर्ण हो गया है। विशाल और बढ़ती ऊर्जा-खपत वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत ऊर्जा सुरक्षा, परिवर्तन मार्गों और स्वच्छ ईंधनों पर अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं में भाग लेता है, और बड़े पैमाने पर कार्यान्वित घरेलू कार्यक्रमों से सीखे गए सबक का लाभ उठाता है।

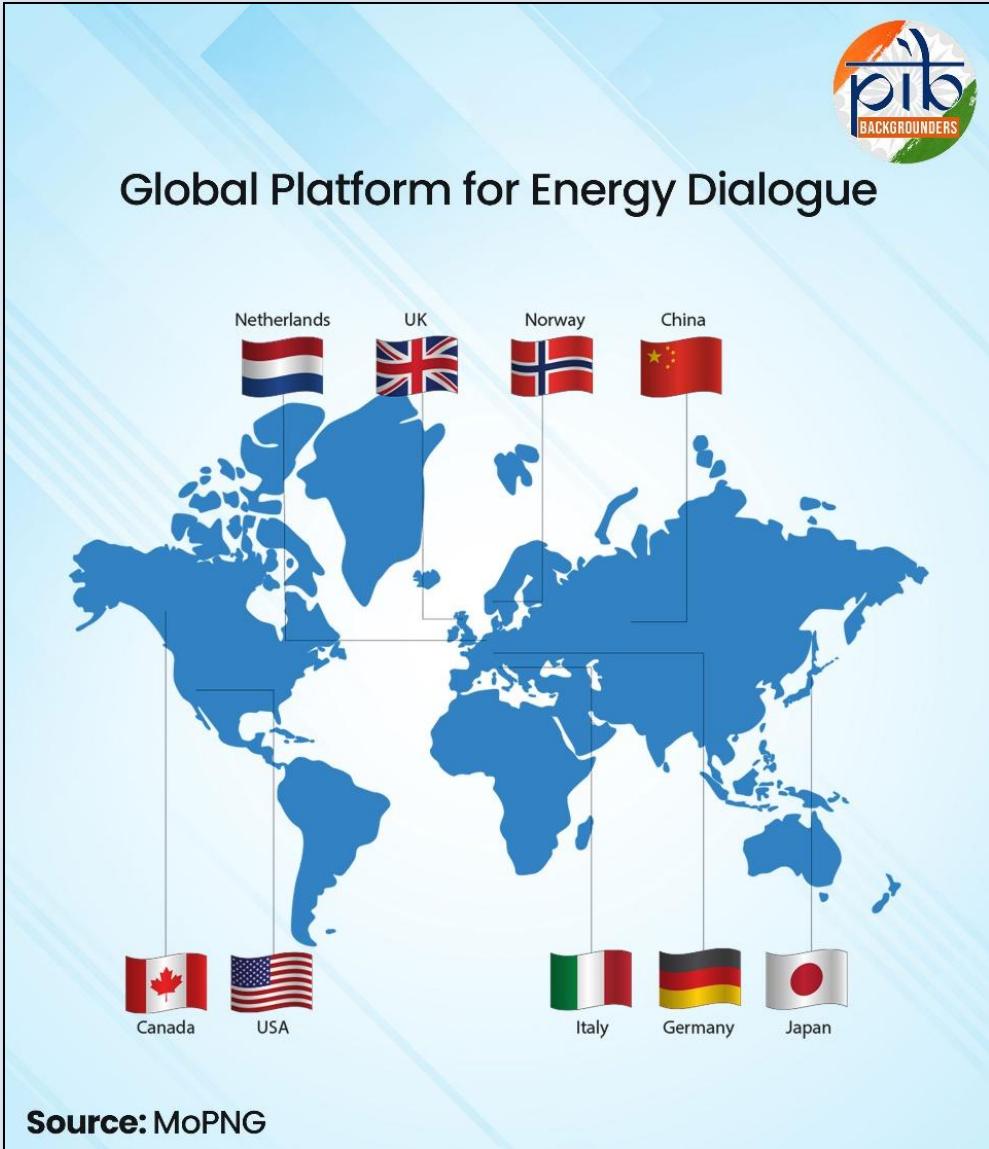
ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस (जीबीए) और जी20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप जैसे मंचों में भारत की भागीदारी ऊर्जा परिवर्तन के लिए व्यावहारिक और समावेशी दृष्टिकोण पर इसके जोर को दर्शाती है। ये सहभागिताएँ जैव ईंधन, वैकल्पिक ईंधन और गैस-आधारित प्रणालियों पर दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करने और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में आपूर्ति विविधीकरण, वहनीयता और उत्सर्जन में कमी से संबंधित मुद्दों की जांच करने के अवसर प्रदान करती हैं।

औपचारिक बहुपक्षीय मंचों के अतिरिक्त, भारत ऊर्जा सप्ताह सरकारों, उद्योग, वित्तीय संस्थानों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बीच संवाद के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। यह आयोजन ऊर्जा बाजारों, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और संक्रमणकालीन मार्गों पर संरचित ज्ञान विनिमय मंचों का समर्थन करता है, जो वर्तमान अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय सहयोगों का पूरक है।

भारत ऊर्जा सप्ताह (आईईडब्ल्यू)

भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन 27 से 30 जनवरी 2026 तक गोवा में चल रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित यह मंच विशेष रूप से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य से, वैशिक ऊर्जा चर्चाओं को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर करता है। वैशिक ऊर्जा बाजारों, भू-राजनीति और जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण समय पर आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक देशों के प्रतिभागी और 6,500 से अधिक सम्मेलन प्रतिनिधि शामिल होंगे।

Global Platform for Energy Dialogue



Source: MoPNG

2023 में शुरू हुआ भारत ऊर्जा सप्ताह वैश्विक ऊर्जा मूल्य शृंखला में अंतरराष्ट्रीय संवाद के लिए मंच के रूप में विकसित हुआ है। इस आयोजन के चौथे संस्करण में ऊर्जा मंत्री, शीर्ष नेता, वित्तीय संस्थान, अंतरराष्ट्रीय संगठन, प्रौद्योगिकी प्रदाता और शैक्षणिक संस्थान ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, वहनीयता और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आएंगे। इसमें उभरती और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रासंगिक दृष्टिकोण शामिल होंगे।

आईईडब्ल्यू 2026 सम्मेलन कार्यक्रम अपने रणनीतिक और तकनीकी सत्रों के माध्यम से नीति-स्तरीय चर्चाओं और कार्यान्वयन-केंद्रित आदान-प्रदान को एक साथ लाता है। ये चर्चाएँ ऊर्जा सुरक्षा, निवेश जुटाना, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ, ऊर्जा समता और ऊर्जा मूल्य शृंखला में परिचालन संबंधी चुनौतियों जैसे विभिन्न मुद्दों पर आयोजित की जाएँगी। इनमें तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, जैव ईंधन, कार्बन कैप्चर, विद्युत प्रणालियाँ और भविष्य की गतिशीलता शामिल हैं।

भारत की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और दूरदर्शी ऊर्जा उद्देश्य मिलकर ऐसे सहयोगात्मक समाधानों के लिए प्रतिबद्धता पर बल देते हैं जो विकास की जरूरतों और जलवायु कार्रवाई के बीच संतुलन बनाए रखते हैं।

निष्कर्ष

नीतिगत सुधारों, अवसंरचना विस्तार और लक्षित स्वच्छ ऊर्जा पहलों के समर्थन से हाल के वर्षों में भारत के ऊर्जा परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। हाइड्रोकार्बन शासन, गैस कनेक्टिविटी, ईंधन और गतिशीलता अवसंरचना, जैव ईंधन और खाना पकाने स्वच्छ ईंधन के क्षेत्र में हुई प्रगति ने ऊर्जा तक पहुंच को मजबूत किया है, प्रणाली की लचीलता में सुधार किया है और उत्सर्जन की तीव्रता को कम किया है। ये घटनाक्रम ऐसे परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जो बढ़ती ऊर्जा मांग का जवाब देते हुए पैमाने, कार्यान्वयन और समावेशन पर जोर देता है।

संदर्भ

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2209478®=3&lang=1>

<https://www.indiaenergyweek.com/>

<https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1896731®=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2212948®=6&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2096817®=3&lang=2>

https://sansad.in/getFile/annex/268/AU2859_W3x2Fj.pdf?source=pqars

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2208694®=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2211769®=3&lang=2>

https://pngrb.gov.in/pdf/press-note/20251216_PR.pdf

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2200386®=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155110®=3&lang=2>

<https://www.pmuy.gov.in/index.aspx>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2208694®=3&lang=1>

विदेश मंत्रालय:

https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/37092/Launch_of_the_Global_Biofuel_Alliance_GBA

विद्युत मंत्रालय:

<https://powermin.gov.in/en/content/energy-transitions-working-group>

सूचना और प्रसारण मंत्रालय:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2094025®=3&lang=2>

विश्व बैंक:

<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/f983c12d-d43c-4e41-997e-252ec6b87dbd/content>

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी):
<https://www.pngrb.gov.in/pdf/TPIAs/HLC 20241028.pdf>

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL):
<https://iocl.com/NewsDetails/59413>

इंडिया ब्रांड इक्विटी फ़ाउंडेशन (IBEF):
<https://www.ibef.org/news/india-to-be-the-world-s-largest-driver-of-energy-demand-growth-by-2035-international-energy-agency-s-iea>

भारी उद्योग मंत्रालय:
<https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1942506®=3&lang=2>

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT):
<https://ncert.nic.in/textbook/pdf/kech203.pdf>

पीआईबी शोध
पीके/केसी/पीबी